

स्टार्टअप्स से सशक्त होता भारत



नवाचार, उद्यमशीलता और अवसरों की नई कहानी लिखता भारत आज दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में उभर चुका है। 1.57 लाख से अधिक डीपीआईआईटी-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स, 100 से ज्यादा यूनिफॉर्म और टियर II/III शहरों से आती नई ऊर्जा ने इस परिवर्तन को ऐतिहासिक बना दिया है। 'स्टार्टअप इंडिया' सहित प्रमुख सरकारी पहलों, मजबूत फंडिंग तंत्र और बढ़ते इनक्यूबेशन नेटवर्क ने लाखों रोजगार सृजित किए हैं और महिला उद्यमिता को नई पहचान दी है। यह केवल स्टार्टअप्स की सफलता की कहानी नहीं बल्कि आत्मनिर्भर और नवाचारी भारत के भविष्य की झलक है।

भा

रत ने 31 दिसंबर, 2024 तक स्टार्टअप की मान्यता के लिए उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा जारी किए गए 1.57 लाख प्रमाणपत्रों के साथ दुनिया के तीसरे सबसे बड़े

स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में खुद को मजबूती से स्थापित किया है। 100 से अधिक यूनिफॉर्म द्वारा संचालित देश का उद्यमशीलता परिदृश्य, नवाचार को फिर से परिभाषित कर रहा है और विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसर पैदा कर रहा है। बंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली-एनसीआर जैसे प्रमुख केंद्र इस परिवर्तन में सबसे आगे रहे हैं, जबकि छोटे शहर भी गति में तेजी से योगदान दे रहे हैं, जिसमें स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से 51% से अधिक स्टार्टअप टियर II/ III शहरों से उभर रहे हैं। स्टार्टअप के लिए प्रमुख योजनाएँ और पहल

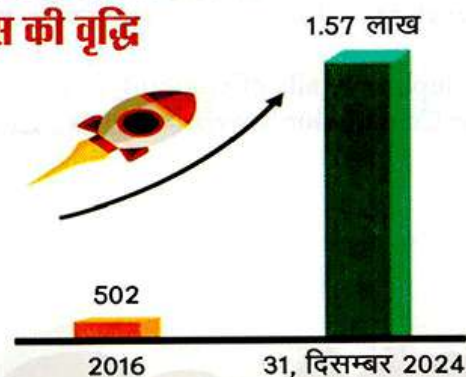
स्टार्टअप इंडिया को भारत सरकार द्वारा 16 जनवरी, 2016 को शुरू किया गया जो नवाचार को बढ़ावा देने और एक संपन्न स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए एक प्रमुख पहल है। इसका लक्ष्य आर्थिक विकास को गति देना और बड़े पैमाने पर

रोजगार के अवसर पैदा करना है। स्टार्टअप को उनकी विकास यात्रा में समर्थन देकर यह पहल नवाचार और डिजाइन को प्रोत्साहित करती है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, इसका उद्देश्य स्टार्टअप को आगे बढ़ाने और सफल होने के लिए सशक्त बनाना है।

प्रगति और असर:

- स्टार्टअप विकास: 31 दिसंबर, 2024 तक डीपीआईआईटी-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या वर्ष 2016 में लगभग 502 से बढ़कर 1,57,706 हो गई है।

DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की वृद्धि





DPIIT
#स्टार्टअप इंडिया

भारत का फलता-फूलता स्टार्टअप इकोसिस्टम



1.57 लाख

स्टार्टअप्स को मान्यता



17.28 लाख

ई-रोजगार



75,935

कम से कम एक महिला
निदेशक वाले स्टार्टअप



- **रोजगार सृजन:** 31 दिसंबर, 2024 तक स्टार्टअप ने 17.28 लाख से अधिक प्रत्यक्ष नौकरियाँ सृजित की हैं, जिसमें आईटी सेवा क्षेत्र 2.10 लाख नौकरियों के साथ सबसे आगे है, जिसके बाद हेल्थकेयर और लाइफसाइंसेज (1.51 लाख) और व्यावसायिक और वाणिज्यिक सेवाएँ (96,474) हैं।
- **महिला-नेतृत्व वाले स्टार्टअप:** 31 दिसंबर, 2024 तक कुल 75,935 मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला निदेशक शामिल हैं (मान्यता प्राप्त स्टार्टअप के स्व-रिपोर्ट किए गए आँकड़ों के अनुसार), जो भारत में महिला उद्यमियों के उदय को दर्शाती हैं।
- **व्यवसाय करने में सुगमता और कर लाभ:** सरलीकृत अनुपालन, स्व-प्रमाणन और तीन वर्षों के लिए कर छूट ने स्टार्टअप के लिए संचालन को सुव्यवस्थित किया है।

स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस)

वर्ष 2021 में एसआईएसएफएस 945 करोड़ रुपये के कोष के साथ शुरू की गई जो विभिन्न चरणों में स्टार्टअप का समर्थन करती है, जिसमें अवधारणा का प्रमाण, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार में प्रवेश और व्यावसायीकरण शामिल हैं। यह योजना 1 अप्रैल, 2021 से शुरू की गई और इसकी देख-रेख विशेषज्ञ सलाहकार समिति (EAC) द्वारा की जाती है, जो फंड आबंटन के लिए इनक्यूबेटर्स का मूल्यांकन और चयन करती है।

- दिसंबर 2024 तक योजना के तहत 213 इनक्यूबेटर्स को मंजूरी दी गई है।

- दिसंबर 2024 तक कुल 2,622 स्टार्टअप को 467.75 करोड़ की फंडिंग से लाभ हुआ है।

फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स (एफएफएस) योजना

स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स (एफएफएस), जिसे जून 2016 में 10,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ शुरू किया गया था, का उद्देश्य स्टार्टअप के लिए घरेलू पूँजी तक पहुँच को बढ़ावा देना है। सिडबी (SIDBI) द्वारा प्रबंधित, यह सेबी-पंजीकृत वैकल्पिक निवेश फंड (एआईएफ) को वित्त पोषित करता है, जो इक्विटी और इक्विटी-लिंक्ड उपकरणों के माध्यम से स्टार्टअप में निवेश करते हैं।

प्रगति और असर:

- वर्ष 2024 तक, डीपीआईआईटी द्वारा सिडबी को 6,886 करोड़ रुपये प्रतिबद्ध किए गए हैं और दिसंबर 2024 तक एफएफएस योजना के तहत सिडबी द्वारा एआईएफ को 11,687 करोड़ रुपये प्रतिबद्ध किए गए थे।
- इस प्रतिबद्धता ने 1173 स्टार्टअप में 21,276 करोड़ रुपये के निवेश को उत्प्रेरित किया।

स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसएस)

स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसएस) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और उद्यम ऋण निधियों से डीपीआईआईटी-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी प्रदान करती है। नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) द्वारा कार्यान्वित, इसका उद्देश्य स्टार्टअप के लिए फंडिंग तक पहुँच को आसान बनाना है, जिसके तहत एक निर्दिष्ट सीमा तक क्रेडिट गारंटी की पेशकश की जाती है।

प्रगति और असर:

- 3 जनवरी, 2025 तक योजना ने 209 स्टार्टअप को 604.16 करोड़ रुपये के 260 ऋणों की गारंटी दी है।
- इनमें से, 27.04 करोड़ रुपये 17 महिला-नेतृत्व वाले स्टार्टअप को आबंटित किए गए हैं।

अन्य उल्लेखनीय योजनाएँ

अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम)

‘अटल इनोवेशन मिशन’ नीति आयोग द्वारा 2016 में शुरू किया गया जिसका उद्देश्य पूरे भारत में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इसमें स्कूल स्तर पर रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए अटल टिकरिंग लैब्स, एक मजबूत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए अटल इनक्यूबेशन सेंटर और असेवित और वंचित क्षेत्रों की सेवा के लिए अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र जैसी पहलें शामिल हैं। अटल न्यू इंडिया चैलेंज राष्ट्रीय प्रभाव वाले उत्पाद और सेवा नवाचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सभी पहलों की निगरानी निरंतर सुधार के लिए तीसरे पक्ष की समीक्षाओं के साथ वास्तविक समय की एमआईएस (MIS) प्रणालियों के माध्यम से की जाती है।

प्रगति और असर:

- आज तक, एआईएम के तहत पूरे भारत के स्कूलों में 10,000 अटल टिकरिंग लैब स्थापित किए जा चुके हैं।
- 18 दिसंबर, 2024 तक 72 अटल इनक्यूबेशन सेंटर्स (एआईसी) में कुल 3,556 स्टार्टअप्स को इनक्यूबेट किया गया है, जिससे 41,965 नौकरियाँ पैदा हुई हैं।

MEITY स्टार्टअप हब (एमएसएच)

भारत लगभग 30,000+ तकनीकी स्टार्टअप्स के साथ सबसे जीवंत स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक है, जो इसे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाता है। MEITY

स्टार्टअप में रोजगार सृजन में अग्रणी उद्योग



आईटी सेवाएँ	2.10 लाख
स्वास्थ्य सेवा एवं जीवन विज्ञान	1.51 लाख
व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक सेवाएँ	96,474
शिक्षा	92,694

के स्टार्टअप हब (एमएसएच) का उद्देश्य प्रौद्योगिकी नवाचार हितधारकों को एकजुट करके और नवाचार व तकनीकी प्रगति के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर एक जीवंत नवाचार और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है। यह एक केंद्रीय हब के रूप में कार्य करता है, जो मंत्रालय द्वारा समर्थित इनक्यूबेशन केंद्रों, उभरती प्रौद्योगिकियों पर उत्कृष्टता केंद्रों और अन्य प्लेटफार्मों के बीच तालमेल सुनिश्चित करता है। एमएसएच पूरे नवाचार और स्टार्टअप इकोसिस्टम में संसाधनों, सर्वोत्तम प्रथाओं और विचारों को साझा करने की सुविधा प्रदान करता है।

प्रगति और असर:

- 5,310+ स्टार्टअप्स, 495+ इनक्यूबेटर्स और 328+ लैब्स MEITY स्टार्ट अप हब (एमएसएच) योजना का हिस्सा हैं।

पिछले 10 वर्षों में, भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में जबरदस्त वृद्धि हुई है और यह दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा बन गया है। स्टार्टअप इंडिया, एसआईएसएफएस, सीजीएसएस, एफएफएस जैसी पहलों और एआईएम और एमएसएच जैसी क्षेत्र विशेष की योजनाओं के साथ सरकार ने नवाचार को बढ़ावा देने, नौकरियाँ पैदा करने और उद्यमियों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। हितधारकों के बीच इस गतिशील सहयोग ने इकोसिस्टम को मजबूत किया है, आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया है और अगली पीढ़ी के नवप्रवर्तकों को सशक्त बनाया है। भविष्य के मद्देनजर भारत का स्टार्टअप परिदृश्य और भी बड़ी उपलब्धियों तक पहुँचने के लिए तैयार है। □

SISFS के तहत इनक्यूबेटर की संघी वृद्धि

